

Fourteenth Loksabha**Session : 10****Date : 08-05-2007****Participants : [Sangwan Shri Kishan Singh](#)**

an>

Title: Need for uniform rate of taxes in grain market in the Country.

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने उठाना चाहता हूँ। दिल्ली के चारों तरफ जो भी प्रांत हैं और जो भी अनाज की मंडियां हैं, वे मार्केट्स बिल्कुल फेल हो गई हैं। उनका सारा व्यापार चौपट हो गया है, व्यापारी बर्बाद हो गए हैं। इसका कारण दिल्ली और आस पास के प्रांतों में इंटर स्टेट कंसाइमेंट टैक्स में फर्क है। दिल्ली में चार परसेंट टैक्स एग्रीकल्चर पर कम लगता है। सेल्स टैक्स दो प्रतिशत कम है। इस छः प्रतिशत के अन्तर के कारण सैकड़ों किलोमीटर से किसान दिल्ली की मंडियों में अपने ग्रेन लाते हैं जिससे किसानों को परेशानी होती है। चूंकि यहां टैक्स में छः प्रतिशत का अन्तर है, इसलिए किसानों को कुछ ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। इसलिए मंडियों में इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है। इसका दूसरा असर यह होता है कि दिल्ली के चारों तरफ जैसा सोनीपत की मंडी है, खरखोदा की मंडी है, बहादुरगढ़ की मंडी है, गुड़गांव की मंडी है, फरीदाबाद की मंडी है, नोयडा की मंडी है, गाजियाबाद की मंडी है, बुलन्दशहर की मंडी है, ये दिल्ली के आस-पास की जितनी मंडियां हैं, वहां का सारा व्यापार और मंडियां फेल हो गयी हैं, वहां के व्यापारी चौपट हो गए हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार यह देखे कि टैक्सेज की जो दरें हैं, वे सभी प्रान्तों में समान हों ताकि व्यापारी बचा रहे और किसानों को घर बैठे फसलों का अच्छा दाम मिल जाए। आस-पास के हजारों व्यापारी बर्बाद हो गए हैं और राज्य सरकारों को भी इसकी वजह से बहुत घाटा हो रहा है। मेरा सुझाव है कि केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और समान टैक्स दर लागू की जाए। [R42]